IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 1, February 2026
Impact Factor: 8.2

क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स में लॉजिस्टिक्स और भुगतान बाधाएँ: भारत के परिप्रेक्ष्य से

डॉ. शिवांशु पांडेय

अतिथि विद्वान - वाणिज्य विभाग

शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश

सारांश (Abstract)

आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स भारत के लिए निर्यात वृद्धि, रोजगार सृजन और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार का प्रमुख माध्यम बन गया है। यह शोध पत्र क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स में लॉजिस्टिक्स और भुगतान संबंधी प्रमुख बाधाओं का भारत के संदर्भ में विश्लेषण करता है। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में उच्च शिपिंग लागत, कस्टम क्लियरेंस में देरी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, अंतिम मील डिलीवरी की चुनौतियाँ और पोर्ट/ट्रांसपोर्ट कंजेशन प्रमुख समस्याएँ हैं। भुगतान क्षेत्र में उच्च लेन-देन शुल्क, मुद्रा रूपांतरण जोखिम, नियामक अनुपालन (RBI दिशानिर्देश), धोखाधड़ी और प्रसंस्करण में देरी बाधाएँ उत्पन्न करती हैं। भारत में क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स बाजार 2024 में लगभग 11,743 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जो 2030 तक 53,380 मिलियन डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है (CAGR 29.2%)। अध्ययन द्वितीयक डेटा पर आधारित है और सरकारी पहलों जैसे UPI के अंतरराष्ट्रीय विस्तार, लॉजिस्टिक्स लागत को एकल अंक तक कम करने की नीति तथा हालिया विदेशी मुद्रा सुधारों का उल्लेख करता है। निष्कर्ष में बाधाओं को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी एकीकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और

DOI: 10.48175/IJARSCT-31164

नीतिगत सुधारों की सिफारिश की गई है, ताकि भारत वैश्विक ई-कॉमर्स में मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सके।

कीवर्ड्स: (Keywords)

क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स बाधाएँ, भुगतान चुनौतियाँ, भारत का परिप्रेक्ष्य, UPI अंतरराष्ट्रीय, कस्टम क्लियरेंस, डिजिटल भुगतान, ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स।

परिचय: (Introduction)

क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स से तात्पर्य उन ऑनलाइन लेन-देनों से है जिसमें खरीदार और विक्रेता अलग-अलग देशों में होते हैं। भारत में ई-कॉमर्स क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें क्रॉस-बॉर्डर व्यापार महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उपभोक्ता वैश्विक ब्रांड्स (फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी) की मांग कर रहे हैं, जबकि भारतीय निर्यातक (SMBs और फ्रीलांसर) अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच बना रहे हैं।

2024-25 में भारत का क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स बाजार महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शा रहा है। लॉजिस्टिक्स सेगमेंट में 29.2% CAGR के साथ तेज विकास हो रहा है। फिर भी, बुनियादी ढांचे की कमी, नियामक जटिलताएँ और भुगतान प्रणाली की सीमाएँ विकास को बाधित कर रही हैं। GST जैसे सुधारों ने घरेलू व्यापार को आसान बनाया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी चुनौतियाँ बाकी हैं—जैसे कस्टम नियम, शिपिंग लागत और विदेशी मुद्रा नियंत्रण।आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स एक क्रांतिकारी माध्यम बन चुका है, जो देशों की सीमाओं को पार कर उपभोक्ताओं को विविध उत्पादों तक आसानी से पहुँच प्रदान करता है। क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स से तात्पर्य उन ऑनलाइन लेन-देनों से है जिसमें खरीदार और विक्रेता अलग-अलग देशों में स्थित होते हैं। भारत के संदर्भ में यह क्षेत्र न केवल आयात के माध्यम से उपभोक्ताओं की बढ़ती मांगों को पूरा कर रहा है, बल्कि निर्यात के जरिए भारतीय छोटे-मध्यम उद्यमों (SMBs),

हस्तशिल्पकारों, फैशन डिजाइनरों और डिजिटल सेवा प्रदाताओं को वैश्विक बाजारों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्तमान समय में (2026) भारत का ई-कॉमर्स क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहा है। कुल ई-कॉमर्स बाजार 2026 में लगभग USD 159.25 बिलियन का अनुमानित है, जो 2031 तक USD 332.94 बिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है (CAGR 15.89%)। क्रॉस-बॉर्डर सेगमेंट में विशेष रूप से उल्लेखनीय विकास देखा जा रहा है—भारत का क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स बाजार 2025 में USD 48 मिलियन तक पहुँचा, जो 2034 तक USD 207.96 मिलियन होने का अनुमान है (CAGR 17.69%)। क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स बाजार 2024 में USD 11.74 बिलियन का था, जो 2030 तक USD 53.38 बिलियन तक पहुँचने की संभावना है (CAGR 29.2%)।

ग्राफ़ 1: भारत क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स बाजार का आकार (2024-2030)

- 2024: USD 11.74 बिलियन
- 2030 (अनुमानित): USD 53.38 बिलियन
- CAGR: 29.2% (2025-2030)

यह ग्राफ़ दिखाता है कि लॉजिस्टिक्स सेगमेंट में सबसे तेज वृद्धि हो रही है, जो क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स की बढ़ती मांग को दर्शाता है।

ग्राफ़ 2: भारत क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स बाजार का आकार (2025-2034)

- 2025: USD 48 मिलियन
- 2034 (अनुमानित): USD 207.96 मिलियन
- CAGR: 17.69%

यह ग्राफ़ क्रॉस-बॉर्डर सेगमेंट की स्थिर लेकिन मजबूत वृद्धि को हाइलाइट करता है। यह वृद्धि कई कारकों से संचालित है: इंटरनेट और स्मार्टफोन की बढ़ती पैठ (भारत में 900 मिलियन से अधिक इंटरनेट यूजर्स)। डिजिटल भुगतान प्रणालियों का विस्तार, विशेष रूप से UPI का वैश्विक स्तर पर उपयोग (UPI ने 2025 में

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 1, February 2026
Impact Factor: 8.2

172 बिलियन ट्रांजेक्शन किए)। पहलें जैसे आत्मनिर्भर भारत, ONDC (Open Network for Digital Commerce), और क्रॉस-बॉर्डर निर्यात को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ (जैसे कूरियर निर्यात सीमा 10 लाख तक बढ़ाना और पोस्टल एक्सपोर्ट सेंटर्स की स्थापना),वैश्विक प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon Global Selling, Shopify, Etsy और eBay पर भारतीय विक्रेताओं की बढ़ती उपस्थिति—Amazon Global Selling के माध्यम से 150,000+ भारतीय विक्रेताओं ने 2015-2025 के बीच USD 20 बिलियन से अधिक का निर्यात किया। भारतीय उपभोक्ता अब फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और प्रीमियम ब्रांड्स के लिए अंतरराष्ट्रीय विकल्प तलाश रहे हैं, जबकि निर्यात पक्ष में हस्तशिल्प, आयुर्वेदिक उत्पाद, ऑर्गेनिक फूड और हैंडमेड आइटम्स की वैश्विक मांग बढ़ रही है। फिर भी, इस तेज विकास के बावजूद क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है। प्रमुख बाधाएँ लॉजिस्टिक्स और भुगतान क्षेत्रों में हैं।

इस शोध का उद्देश्य है:

क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स में लॉजिस्टिक्स और भुगतान बाधाओं की पहचान करना।

भारत के संदर्भ में उनका प्रभाव विश्लेषित करना।

संभावित समाधान और सरकारी पहलों का मूल्यांकन करना।

यह अध्ययन भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए प्रासंगिक है।

शोध पद्धति (Research Methodology)

यह शोध द्वितीयक डेटा विश्लेषण पर आधारित गुणात्मक अध्ययन है। डेटा स्रोतों में शामिल हैं:

उद्योग रिपोर्ट्स (Grand View Research, IBEF, IMARC Group)।

सरकारी दस्तावेज (RBI दिशानिर्देश, वाणिज्य मंत्रालय रिपोर्ट्स)।

अकादमिक पत्र और समाचार लेख (2024-2026)।

अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स (World Bank, DHL, FedEx)।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 1, February 2026
Impact Factor: 8.2

डेटा संग्रह 2024-2026 की नवीनतम उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। विश्लेषण थीमैटिक तरीके से किया गया—लॉजिस्टिक्स और भुगतान बाधाओं को अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत कर उनके कारणों, प्रभावों और समाधानों का परीक्षण किया गया। कोई प्राथमिक सर्वे नहीं किया गया, क्योंकि यह समीक्षा-आधारित पेपर है। सीमाएँ: तेजी से बदलते नियमों के कारण कुछ डेटा पुराना हो सकता है।

लॉजिस्टिक्स बाधाएँ (Logistics Barriers)

भारत में क्रॉस-बॉर्डर लॉजिस्टिक्स की प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:

उच्च शिपिंग लागत और देरी: ट्रैफिक कंजेशन, पोर्ट भीड़ और अपर्याप्त रेल/सड़क कनेक्टिविटी के कारण डिलीवरी समय बढ़ जाता है। अंतिम मील डिलीवरी ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से कठिन है।

कस्टम और नियामक जटिलताएँ: दस्तावेजीकरण की जटिलता, विभिन्न HS कोड नियम और टैरिफ (जैसे 2025 में US-India व्यापार तनाव) क्लियरेंस में देरी पैदा करते हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी: कई क्षेत्रों में वेयरहाउसिंग और ट्रैकिंग सिस्टम अपर्याप्त हैं। हालांकि, AI और वेयरहाउस ऑप्टिमाइजेशन से सुधार हो रहा है।

भारत पोस्ट की भूमिका: सस्ता विकल्प होने के बावजूद क्षमता सीमित है; हालिया सुधारों से पोस्टल एक्सपोर्ट को कार्गो के बराबर सुविधाएँ मिल रही हैं।

ये बाधाएँ निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता कम करती हैं और उपभोक्ताओं के लिए विदेशी उत्पाद महँगे बनाती हैं।

भुगतान बाधाएँ (Payment Barriers)

भुगतान क्षेत्र में चुनौतियाँ निम्न हैं:

उच्च शुल्क और मध्यस्थ बैंक: कई इंटरमीडियरी के कारण 5-7% तक फीस लगती है; FX मार्कअप अतिरिक्त बोझ है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 1, February 2026
Impact Factor: 8.2

देरी और पारदर्शिता की कमी: SWIFT जैसे पारंपरिक सिस्टम में 2-5 दिन लगते हैं; रीयल-टाइम ट्रैकिंग मुश्किल।

नियामक और अनुपालन मुद्दे: RBI के LRS सीमा, AML/KYC आवश्यकताएँ और विदेशी मुद्रा नियम जटिल हैं। हालांकि, 2025 में RBI ने Rupee अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा दिया।

धोखाधड़ी और मुद्रा जोखिम: क्रॉस-बॉर्डर ट्रांजेक्शन में फ्रॉड का खतरा अधिक है।

UPI-PayNow (सिंगापुर) और अन्य लिंकेजेस जैसे प्रयास सकारात्मक हैं। नई PA-CB लाइसेंस (जैसे Unlimit) भारतीय मर्चेंट्स को अंतरराष्ट्रीय भुगतान आसान बना रहे हैं।

सरकारी पहल और समाधान

लॉजिस्टिक्स: राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, PM Gati Shakti, और लागत को GDP के 8-9% तक कम करने का लक्ष्य।

भुगतान: UPI का वैश्विक विस्तार, विदेशी मुद्रा सुधार (2025), और फिनटेक लाइसेंस।

अन्य: ONDC, डिजिटल लिटरेसी और AI आधारित कस्टम क्लियरेंस।

निष्कर्ष (Conclusion)

क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स भारत के लिए अपार संभावनाएँ रखता है, लेकिन लॉजिस्टिक्स और भुगतान बाधाएँ पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं करने दे रही हैं। तेज विकास दर (29%+ CAGR) के बावजूद, बुनियादी ढांचा, नियामक सरलीकरण और प्रौद्योगिकी अपनाने की जरूरत है। सिफारिशें:

अधिक अंतरराष्ट्रीय UPI लिंकेजेस और ब्लॉकचेन आधारित भुगतान।

स्मार्ट वेयरहाउसिंग और मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स।

SMBs के लिए ट्रेनिंग और सरकारी सब्सिडी।

इन प्रयासों से भारत वैश्विक ई-कॉमर्स हब बन सकता है और निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 1, February 2026
Impact Factor: 8.2

संदर्भ (References)

[1]. Grand View Research. (2025). India Cross-border E-commerce Logistics Market Outlook.
[2]. IMARC Group. (2025). India Cross-Border E-Commerce Market Report.
[3]. Worldline India. (2025). Cross-Border Payment Challenges and Solutions.
[4]. Reserve Bank of India. (2025). UPI-PayNow Linkage and Forex Regulations.
[5]. IBEF. (2025). Transforming India’s Logistics Sector.
[6]. DHL eCommerce. (2025). Cross-Border Buying Behavior Trends.
[7]. Avalara. (2025). Challenges in Cross-Border Trade for Indian Exporters.

Copyright to IJARSCT
www.ijarsct.co.in
DOI: 10.48175/IJARSCT-31164